ISSN 2395-031X

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् वैश्विक प्रगति एवं इससे उत्पन्न चुनौतियाँ

डॉ. प्रदीप श्रीवास्तव
सहा. प्राध्यापक - वाणिज्य विभाग
शासकीय महाविद्यालय, बण्डा

सारांश -

निश्चित ही भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आजादी के 75 वर्षों में व्यवसायिक प्रगति से न केवल सोने की चिड़िया वाली छवि को वापस प्राप्त किया इस है, बल्कि 1991 की नवीन आर्थिक नीति को क्रियान्वित कर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत ने अपना परचम लहराया है। प्राचीन काल से भारतवर्ष का बड़े पैमाने पर विदेशों से व्यापार होने के प्रमाण मिलते हैं। विश्व के विभिन्न देशों ने स्थल मार्ग व जल मार्ग दोनों से भारत के साथ व्यापार किया है। विश्व स्तरीय वस्तुओं के निर्माण एवं विनिमय से भारत विश्व में सोने की चिड़िया के नाम से अपनी पहचान प्राप्त कर चुका था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत की सबसे बड़ी चुनौती अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस प्राप्त करने की थी, जिसके लिए सरकारों द्वारा सतत् प्रयास किए गए भारत सरकार द्वारा 1991 में प्रारंभ आर्थिक नियोजन कार्यक्रम के द्वारा देश की समग्र व संतुलित विकास हेतु पंचवर्षीय योजना के माध्यम से कार्य प्रारंभ किया गया। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत ने नवीन आर्थिक नीति, औद्योगिक नीति एवं व्यापार के नए आयामों एवं नवप्रवर्तन के द्वारा व्यवसाय के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में जहाँ एक ओर निर्यात में वृद्धि तो वहीं दूसरी ओर आयातों में निरंतर कमी आई है साथ ही भुगतान संतुलन पक्ष में हुए हैं। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत जहां एक ओर अनेक उपलब्धियां हासिल हुई, वहीं दूसरी ओर इन उपलब्धियों के साथ कुछ चुनौतियाँ भी सामने आई । प्रमुख चुनौतियों के रूप में उपभोक्ताओं का शोषण, सामाजिक पारस्परिक संबंधों में कमी, बढ़ता पर्यावरण असंतुलन, कानूनों का बढ़ता दुरुपयोग, बढ़ती कर चोरी, बढ़ता साइबरक्राइम आदि चुनौतियां सामने आई। आवश्यक सुझाव परिवर्तन प्रकृति के नियम हैं अतः समय के अनुसार हुए परिवर्तनों को स्वीकार करना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है चाहे बात व्यापार के स्वरूपों में परिवर्तन की हो या व्यापार के नए आयामों को स्वीकार करने की हो दोनों ने व्यापार की प्रगति में सतत् वृद्धि की है परंतु उक्त वृद्धि से कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हुई है जिन्हें हम चुनौतियों के रूप में देख रहे हैं यदि हम कुछ उपायों पर अमल करें तो निश्चित ही इन चुनौतियों का सामना करने में हम सफल होंगे।

मुख्य शब्द - अर्थव्यवस्था, विनियोजित, उदारीकरण, लालफीताशाही

ISSN 2395-051X

प्राचीन काल से भारत वर्ष का बड़े पैमाने पर विदेशों से व्यापार होने के प्रमाण मिलते हैं। विश्व के विभिन्न देशों ने स्थल मार्ग और जलमार्ग दोनों से भारत के साथ व्यापार किया है। भारत में उत्पन्न मसाला, मोती, हीरे, जवाहरात, हाथी दाँत, औषधियाँ, वस्त्र (विशेष रुप से सूती, ऊनी व सिल्क) आदि वस्तुओं की आपूर्ति विश्व के विभिन्न देशों को प्रमुख रुप से की है। भारतीय कपड़े की विदेशों में बड़ी माँग हुआ करती थी व विश्व के लगभग हर भाग में भारत से कपड़ा विक्रय हेतु जाता था। ढाका की मलमल विश्व प्रसिद्ध थी। इसका धागा बहुत ही पतला होता था जो कि चरखे पर हाथ से काटा जाता था, इस मलमल की खूबी हुआ करती थी कि पूरा का पूरा थान अँगूठी के बीच से निकल जाता था।

विश्व स्तरीय वस्तुओं के निर्माण एवं विनिमय से भारत सोने की चिड़िया के नाम से अपनी पहचान प्राप्त कर चुका था, किन्तु इस छवि पर बहुत जल्द ही ग्रहण लगना शुरु हो गया और इसके दुष्परिणाम भारत को उठाना पड़े। सर्वप्रथम जब इस्लाम का उदय हुआ तो अरब, फारसी, मिस्त्र और मध्य एशिया के विविध देशों में इस्लाम का प्रसार हुआ परिणामतः भारत के स्थल एवं जल मार्गों पर मुस्लिम साम्राज्य का अधिकार हो गया जिससे भारत का व्यापार अरब निवासियों के हाथ में चला गया। तत्पश्चात् पुर्तगालियों ने भी भारत में व्यापार करना प्रारंभ कर दिया।

अंग्रेजों का भारत में आगमन व ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा व्यापार की शुरुआत भारत की वैश्विक प्रगति पर पूर्ण ग्रहण की स्थिति में तब्दील हो गई। अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं को आपस में लड़ाकर न केवल भारत के व्यापार को छीना बल्कि भारतीय साम्राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। अब भारत में उत्पन्न वस्तुएँ मात्र कच्चा माल बनकर रह गयीं थीं। भारतीय प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त बहुकीमती वस्तुएँ कच्चे माल के रुप में इग्लैंड को भेजना व वहाँ पर निर्मित वस्तुओं को ऊँचे दामों पर बेचकर भारत के खजाने खाली कर आर्थिक रुप से दिवालिया बनाना ही ब्रिटिश हुकुमत का लक्ष्य बन गया जिसकी पूर्ति हेतु अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों में बड़े पैमानों पर पूँजी विनियोजित कर भारतीय व्यवसाय पर पूरी तरह से अपना वर्चस्व कायम कर लिया और लगभग 200 वर्षों तक भारत पर राज किया जिससे अंग्रेजों की गुलामी ने भारतीय व्यवसाय जगत को पंगु बना दिया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत की सबसे बड़ी चुनौती अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापिस प्राप्त करने की थी जिसके लिए सरकारों द्वारा सतत् प्रयास किये गये जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम 1948 में औद्योगिक नीति की घोषणा कर भारतीय अर्थव्यवस्था को आर्थिक आत्मनिर्भर बनाने ऋण बोझ को कम करने एवं औद्योगिक प्रगति से देश को समग्र एवं संतुलित विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का निश्चित किया गया।

भारत सरकार द्वारा 1951 में प्रारंभ आर्थिक नियोजन कार्यक्रम के द्वारा देश के समग्र व संतुलित विकास हेतु पंचवर्षीय योजना के माध्यम से कार्य प्रारंभ किया गया। जिसके अंतर्गत द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक प्रगति को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया। इस योजना में भारी उद्योग स्थापित करने का कार्य प्रारंभ किया गया।

लौह तथा इस्पात, कोयला, उर्वरक, भारी इंजीनियरिंग के सामान और भारी बिजली के सामान के उद्योगों में अभूतपूर्व प्रगति हुई। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में लौह इस्पात के कराखाने स्थापित किये गये। इसी प्रकार आगामी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश में औद्योगिक विकास की दर में स्थाई एवं निरंतरता से देश के संतुलित विकास हेतु अनेक कार्यक्रम एवं योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। विशेष तौर से नई आर्थिक नीति 1991 की बात की जाए तो इसमे लागू उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की अवधारणा ने भारतीय अर्थव्यवस्था को औद्योगिक प्रगति में बुलंदियों पर पहुँचाया है। उदारीकरण के द्वारा राष्ट्र में व्याप्त औद्योगिक रुग्णता भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता एवं बढ़ती हुई मुद्रा स्फीति जैसी समस्याओं का निराकरण किया गया, साथ ही निजीकरण के द्वारा नवीन उद्यमियों को आर्थिक विकास हेतु समान अवसर उपलब्ध कराये गये जिससे भारी पूँजी विनियोग की उपलब्धता, अनावश्यक राजनैतिक हस्तक्षेप, सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त नौकरशाही, लालफीताशाही जैसी बुराईयों से छुटकारा मिला। वैश्वीकरण के द्वारा विश्वकुटुम्बकम की भावना को सकारता प्रदान की गई । इस प्रकार 1991 की आर्थिक नीति के अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक क्षेत्र में स्वावलंवी एवं विदेशी प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया।

1990 के दशक के पूर्व आम उपभोक्ताओं ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि हमें वस्तु खरीदने हेतु बाजार नहीं जाना होगा वल्कि बाजार ही हमारे घर सामान लेकर आ जाएगा। इस अकल्पनीय तथ्य को वास्तविकता में वदलते हुए भारत में सन् 1990 के दशक में प्रचलित ई-कॉमर्स अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य या इलेक्ट्रॉनिक व्यापार ने भारत में व्यवसाय जगत की दिशा एवं दशा वदल दी । वैसे तो इस प्रकार के व्यवसाय की शुरुआत एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) मूल्य वर्जित नेटवर्क (वैन) के माध्यम से 1960 के दशक में शुरु की गई थी किन्तु भारत में ई-कॉमर्स की व्यवस्थित एवं वृहद शुरुआत 1990 के दशक से चलन में आई, जो कि आगामी दशकों में निरंतर बढ़ती गई और (एक रिपोर्ट के अनुसार) उम्मीद की जा रही है कि इसी क्रम में इसका आकार बढ़ता रहा तो 2030 तक 40 विलियन डालर तक ये व्यवसाय पहुँच जाएगा।

ई-कॉमर्स एक ऐसी कार्यप्रणाली है जिसके माध्यम से इंटरनेट का प्रयोग कर सामान खरीदने व वेचने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार के व्यापार ने सरकार की उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की अवधारणा को साकार वनाने का कार्य किया है। व्यवसाय जगत से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से जुड़े सभी पक्षकारों को अनेक प्रकार से लाभांवित करने का कार्य ई-कॉमर्स के द्वारा संभव है। 24 घंटे 07 दिन क्रेता व विक्रेताओं के मध्य की दूरी को कम करते हुये न्यूनतम लागतों पर वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता का कार्य ई-कॉमर्स द्वारा संभव हो सका है।

व्यवसाय से उपभोक्ता को (B toC) व्यवसाय से व्यवसाय को (B to B) उपभोक्ता से उपभोक्ता को (C to C) एवं सरकार से उपभोक्ता को (E to C) इस प्रकार 5 स्तरों में ई-कॉमर्स का व्यवसाय संचालित है।

इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत ने नवीन आर्थिक नीति, औद्योगिक नीति एवं व्यापार के नये आयामों एवं नवप्रर्वतन के द्वारा व्यवसाय के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था

में जहाँ एक ओर निर्यातों में वृद्धि हुई तो वहीं दूसरी ओर आयातों में निरंतर कमी आई है। साथ ही भुगतान संतुलन पक्ष में हुये हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय अर्थ व्यवस्था में जहाँ एक ओर निरंतर औद्योगिक उपलब्धियाँ हासिल कर वैश्विक प्रगति में सतत् एवं स्थायित्व प्राप्त हुआ है तो वहीं दूसरी ओर व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में निरंतर गिरावट आई है जो कि सम्पूर्ण व्यवसाय जगत के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है।

प्रमुख चुनौतियाँ -

⇨ उपभोक्ताओं का शोषण -बढ़ती अनैतिक प्रतिस्पर्धा के चलते मिलावट, झूठे विज्ञापन, अवैधानिक कृत्य, अनुचित मूल्य, काला-बाजारी आदि के द्वारा उपभोक्ता का शोषण किया जा रहा है। अत्याधिक मात्रा में रसायनिकों के प्रयोग द्वारा अधिक मात्रा में उत्पादन कर उपभोक्ताओं को की जाने वाली आपूर्ति मानव जीवन एवं स्वास्थ्य पर प्रातेकूल प्रभाव डाल रही है।

⇨ सामाजिकता एवं पारस्परिक संबंधो में कमी - ये सत्य है कि व्यवसाय के नये आयामों से विशेष तौर से ई-कॉमर्स से व्यवसाय में वृद्धि हुई है एवं ग्राहकों घर बैठे माल की प्राप्ति होने लगी है। किन्तु हमारी वर्षों पुरानी सामाजिक सद्भाव एवं समरसता की संस्कृति का निंरतर पतन प्रारंभ हो चुका है। उपभोक्ता एवं व्यापारी के बीच जो मधुर संबंध होते थे या व्यवसायी के जो सामाजिक दायित्व निर्धारित किये गये थे, उनके औचित्य पर अब प्रश्न चिन्ह लग चुका है। चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है इसलिए व्यवसायी एक ग्राहक के बीच सामाजिक संबंधों का मधुर होना नितांत आवश्यक है।

⇨ बढ़ता पर्यावरण असंतुलन -भारत की वैश्विक प्रगति एवं व्यवसाय के क्षेत्र मे नवप्रर्वतन के द्वारा भारत का पर्यावरण बड़ी मात्रा में असंतुलित हुआ है। औद्योगिकीकरण के चलते नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति, व्यवसायिक क्षेत्रों का उन्नयन, बड़े पैमाने पर उत्पादन आदि ने पर्यावरण को बड़ी मात्रा में प्रदूषित किया है। भारत के महानगरों में आज व्यक्ति का स्वस्थ रहना चुनौती पूर्ण हो गया है। भारत जैसे प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण देश में आज औद्योगिक प्रगति के नाम पर प्राकृतिक वस्तुओं के स्थान पर कृत्रिम वस्तुएँ उपयोग की जा रही है। बात चाहे मिनरल वाटर की हो या पैकिट में बंद दूध की हो, बढ़ती मात्रा में प्लास्टिक के उपयोग की हो, ये हमें किसी चुनौती से कम नहीं।

⇨ कानूनों का बढ़ता दुरुपयोग - आजादी के 75 वर्ष में बहुत वैश्विक प्रगति हुई है, साथ ही बहुत से कानून भी बने लेकिन इन कानूनों के उल्लघनों की बात आए तो उल्लघनों की प्रगति वैश्विक प्रगति से भी अधिक दर से हुई है। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा निज स्वार्थ के चलते बालश्रम, बंधक श्रम, न्यूनतम वेतन, औद्योगिक विवाद जैसे अधिनियमों का खुले आम उल्लघंन किया है। शासन द्वारा भले ही प्रत्यक्ष रुप से कानूनों मे परिवर्तन कर इंस्पेक्टर राज कागजों पर सामप्त कर दिया हो लेकिन अप्रत्यक्ष रुप से इंस्पेक्टर राज भारतीय व्यवसाय जगत में अभी भी व्याप्त है ऐसे में कानूनों को लागू कर उनका पालन करवाना किसी चुनौती से कम

नहीं है।

⇨ बढ़ती कर चोरी -भारत में जिस दर से व्यवसायिक प्रगति हुई है उस दर से कर राजस्व की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। सरकार के द्वारा आरोपित अप्रत्यक्ष कर का बहुत बड़ा भाग कर अपवंचन के रुप में जा रहा है, यदि सही मायने में आरोपित कर की वसूली होने लगे तो न केवल करों की निर्धारित वर्तमान दरों में कमी होगी बल्कि बहुत कुछ वस्तुएँ करमुक्त माल की सूची में सम्मिलित हो सकती हैं। बढ़ती कर चोरी की प्रवृत्ति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए किसी चुनौती से कम नहीं।

⇨ बढ़ते सायबर क्राइम -स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् व्यवसाय के क्षेत्र में तकनीकी प्रौद्योगिकी का तेजी से प्रयोग हुआ है। परिणामतः ई-कॉमर्स के रुप में व्यापार के नये आयाम का जन्म हुआ एवं ई-कॉमर्स ने व्यापार को एक नई दिशा प्रदान की है। किन्तु भारत में इस व्यापार से साइबर क्राइम के रुप में एक नई समस्या प्रारंभ हो गयी है। भारतीय नगारिकों की तकनीकी अज्ञानता एवं सरल व सादगीपूर्ण जीवनशैली के कारण सहजता से किसी भी अनजान व्यक्ति पर न केवल भरोसा कर लेना बल्कि उससे निजी व गोपानीय बातें भी साझा कर लेने के चलते दिन-प्रतिदिन साइबर क्राइम के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं। बढ़ता हुआ साइबर क्राइम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।

सुझाव -परिवर्तन प्रकृति का नियम है अतः समय के अनुसार हुये परिवर्तनों को स्वीकार करना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है बात चाहे व्यापार के स्वरुपों में परिवर्तन की हो या व्यापार के नये आयामों को स्वीकार करने की हो दोनों ने ही व्यापार की प्रगति में सतत् वृद्धि की है परंतु उक्त वृद्धि से कुछ समस्याएँ भी उत्पन्न हुई हैं जिन्हें हम चुनौती के रुप में देख रहे हैं। यदि हम कुछ उपायों पर अमल करें तो निश्चित ही इन चुनौतियों का सामना करने में हम सफल होंगे।

1. उपभोक्ताओं का शोषण आदिकाल से हुआ है और अभी भी यह समस्या व्याप्त है लेकिन हम शिक्षा के स्तर में सुधार करके एवं लोगों की जागरुकता में वृद्धि कर इस समस्या से निजात पा सकते हैं अतः आवश्यकता है कि लोगों को जागरुक बनाने हेतु दृश्य एवं श्रव्य संचार माध्यमों से, समाचार पत्रों से, नुक्कड़ नाटकों के प्रयोग से जनजागृति की है।

2. तकनीकी के निरंतर प्रयोग से हमारी प्रत्यक्ष दूरियाँ बढ़ी हैं परिणामतः सामाजिक एवं पारस्परिक संबंधों में कमी आई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह बढ़ती हुई तकनीकों का दुष्परिणाम है यदि हम लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में बतायें व उसे अपनायें तो नागरिकों में प्रत्यक्ष रुप से तो संबंध मधुर होंगे ही साथ ही तकनीकी के माध्यम से अप्रत्यक्ष रुप से सम्पर्कों में वृद्धि होगी जिससे सामाजिक व पारस्परिक संबंधों का दायरा बढ़ता जाएगा।

3. यह सच है कि हमारा पर्यावरण निरंतर असंतुलित होता जा रहा है लेकिन इसका एकमात्र कारण वैश्विक प्रगति को नहीं माना जा सकता है। हमें अपनी शिक्षण व्यवस्था में पर्यावरण जैसे विषयों पर अधिकतम ध्यान देना होगा। लोगों को पर्यावरण की महत्ता से अवगत कराने हेतु पर्यावरण की शिक्षा देना, जन जागरुकता

ISSN 2395-051X

अभियान चलाना, पर्यावरण संतुलन हेतु उपायों का प्रचार-प्रसार करना व इस संबंध में आवश्यक कानून बनाना, कानूनों में संशोधन करना एवं कानूनों का सख्ती से पालन करना जरुरी है।

4. आज भारत वर्ष में बहुत बड़ी मात्रा में कानून पारित किये जा चुके हैं किन्तु इन कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है क्योंकि व्यवसायियों के द्वारा अज्ञानतावश इन कानूनों का समुचित रुप से पालन करना व्यवहारिक रुप से कठिन है जिसके परिणाम स्वरुप इंस्पेक्टर राज जैसी बुराई जन्म ले रही है अतः आवश्यकता इस बात की है कि इन कानूनों के व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन कर इनमें संशोधन की आवश्यकता है। व्यवसायिक कानून या श्रम कानूनों के कर कानूनों का सख्ती से पालन कर एवं उद्गम स्थान पर कर कटौती को अधिक प्रभावी बना कर चोरी को रोका जा सकता है।

5. नागरिकों को नवीन तकनीकी के प्रयोग से संबंधित आधारभूत ज्ञान एवं जागरुकता बढ़ाकर साइबर क्राइम से बचाया जा सकता है।

निष्कर्ष -अंत में निष्कर्ष के रुप में कहा जा सकता है कि आजादी के 75 वर्षों में औद्योगिक प्रगति की दर में निरंतर वृद्धि हुई है और भारत ने व्यवसाय के क्षेत्र में सोने की चिड़िया वाली छवि को पाने में सफलता प्राप्त की है। हालाँकि यह कटु सत्य है कि वैश्विक प्रगति में अनेक चुनौतियाँ हमारे सामने है किन्तु आवश्यक सुझावों पर अमल कर न केवल चुनौतियों का सामना किया जा सकता है बल्कि अपने लक्ष्य तक पहुँचा जा सकता है।

सन्दर्भ -

1. सिन्हा, डॉ. वी.सी. एवं सिन्हा डॉ. पुष्पा; व्यवसायिक पर्यावरण, एस.वी.पी.डी. पब्लिशिंग हाउस आगरा, 2009
2. जैन, डॉ. जिनेन्द्र कुमार एवं पुणताम्बेकर, डॉ. जी.एल.; व्यवसायिक पर्यावरण मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 2016
3. मिश्रा, डॉ. जी.पी.; भारतीय अर्थव्यवस्था, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2021
4. पुरी, वी.के. एवं मिश्र एस.के.; भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालया पब्लिकेशन हाउस, 2014
5. दत्त, रूद्र एवं सुन्दरम के.पी.एम.; भारतीय अर्थव्यवस्था, एस. चन्द एण्ड कम्पनी लि., नई दिल्ली, 1998